

कांग्रेस ने सचिन पायलट को ‘‘फील्ड’’ किया, जातिगत जनगणना को केवल दिखावा साबित करने के लिए

पायलट ने एआईसीसी में आयोजित प्रैस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केवल बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने ‘‘कास्ट सैन्सस’’ को अपनाने का ‘‘नाटक’’ किया है, क्योंकि जात का भारी महत्व रहा है मतदान में

–रेणु मि्तल–
–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–
नई दिल्ली, 17 जून। कांग्रेस ने आज ओबीसी समुदाय के अपने प्रमुख नेताओं में से एक सचिन पायलट को आगे कर जातीय जनगणना के मुद्दे पर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला तथा इससे जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस विषय पर गंभीर नहीं है और लोगों की आंखों में धूल झाँकने का प्रयास कर रही है।

एआईसीसी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि केन्द्र सरकार, जो अब तक जातीय जनगणना को पूरी तरह नकारती रही, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे शहरी नक्सल का काम कहा था और राज्य मंत्री ने इसे स्वीकार करने से इनकार किया, वह भी राहुल गांधी और कांग्रेस के भारी दबाव में आकर आखिरकार इसे स्वीकारने को मजबूर हुई।

पायलट ने बताया कि सरकार द्वारा

■ पायलट ने अपनी इस सोच के समर्थन में दो तर्क पेश किये। पहला तर्क है, केन्द्रीय सरकार ने देश भर में ‘‘कास्ट सैन्सस’’ कराने के लिए केवल 574 करोड़ रुपये का ही प्रावधान किया है, जबकि इस काम को ढंग से कराने के लिए 8 से 10,000 करोड़ रुपये की लागत आने का आंकलन है। इतना कम बजटीय प्रावधान, ‘‘कास्ट सैन्सस’’ कराने के बारे में केन्द्र सरकार के गैर गंभीर होने का प्रमाण है।

■ पायलट का दूसरा तर्क है, केन्द्रीय सरकार 2027 में यह ‘‘कास्ट सैन्सस’’ कराना चाहती है। दो साल का विलंब क्यों? सचिन का कहना है, एक बार चुनाव हो जाए, उसके बाद ‘‘कास्ट सैन्सस’’ का मुद्दा आसानी से ठंडे बस्ते में डाल दिया जा सकता है, जैसे, महिला आरक्षण विधेयक ठंडे बस्ते में डाला हुआ है।

जारी की गई जनगणना अधिसूचना में जाति जनगणना का कोई उल्लेख नहीं है और इसके लिए बजट में महज 574 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, जबकि इसकी वास्तविक लागत 8,000 से 10,000 करोड़ रूपए के

बीच होगी।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि जातीय जनगणना तेलंगाना मॉडल पर हो, जहाँ विशेषज्ञों से सलाह लेकर ऐसा फॉर्मेट तैयार किया गया, जिसमें शैक्षणिक योग्यता, आर्थिक स्थिति,

जीविका का स्वरूप, सरकारी नौकरियों में भागीदारी और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल की गई।

सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण विधेयक की तरह ही सरकार जाति जनगणना के मामले में भी आँख मिचाली खेल रही है और वहाँ के लोग अन्य बिन्दु से कहीं ज्यादा जाति के आधार पर ही मतदान करते हैं।

पायलट ने एक और अहम मुद्दा उठाया, जनगणना वर्ष 2027 में क्यों कराई जा रही है, जबकि इसमें अभी दो साल का समय शेष है। इससे स्पष्ट है कि सरकार इस मुद्दे को लगातार टाल रही है और इसमें उसकी कोई रुचि नहीं है। यह सिर्फ कांग्रेस के दबाव का नतीजा है कि सरकार को यह कदम उठाना पड़ा।

इण्डस वॉटर ट्रीटी से प्राप्त सरप्लस पानी को राजस्थान तक लायेगी भारत सरकार

इसके लिए भारत सरकार 113 किलोमीटर लम्बी नहर बनायेगी, यह नहर चिनाब-रावी-ब्यास-सतलज नदियों को जोड़ते हुए जम्मू-कश्मीर का सरप्लस पानी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सूखी धरती तक पहुँचायेगी

–जाल खंबाता–
–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–
नई दिल्ली, 17 जून। जल कूटनीति और रणनीतिक संसाधन योजना में उठाये गये एक बड़े कदम के तहत, भारत ने सिंधु नदी प्रणाली के अतिरिक्त जल की पाकिस्तान को होने वाली आपूर्ति पूरी तरह से रोकते हुए, देश में ही इसका और उपयोग करने की एक बड़ी योजना बनाई है।

सरकार जम्मू-कश्मीर से 113 किलोमीटर लंबी नहर बनाकर अतिरिक्त जल को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में मोड़ने की योजना बना रही है।

इसके साथ ही केन्द्र सरकार ने लंबे समय से लंबित उड़ा बहुउद्देश्यीय परियोजना को जम्मू के कठुआ में पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य जलविद्युत उत्पादन के साथ-साथ, सिंचाई और पेयजल की

■ जैसा कि विदित ही है, वर्तमान में भारत का नहर सिस्टम, सतलज, ब्यास नदी का पानी इंदिरा गांधी नहर के मार्फत राजस्थान के गंगानगर इलाके तक पहुँचाता है।

■ नई 113 किलोमीटर लंबी नहर भी इंदिरा गांधी नहर सिस्टम का उपयोग करते हुए अब इण्डस वैली वॉटर सिस्टम का सरप्लस पानी गंगानगर तक पहुँचायेगी।

■ भारत सरकार बहुप्रतीक्षित व प्रस्तावित कथुआ हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भी नए सिरे से शुरू करते हुए, कथुआ बाँध के पानी से बिजली ही पैदा करेगी, साथ ही इस बाँध के पानी का उपयोग सिंचाई व पीने के पानी की परियोजनाओं में काम में लेगी।

आपूर्ति बढ़ाना है। प्रस्तावित चिनाब–रावी–ब्यास–सतलज नहर इन नदियों के जल नेटवर्क को एक साथ जोड़ देगी, जिससे पाकिस्तान की ओर बहने वाले जल की मात्रा कम हो जाएगी। शनिवार को केन्द्रीय गृह मंत्री

अमित शाह ने घोषणा की कि ‘‘सिंधु जल को प्रस्तावित नहर के माध्यम से राजस्थान के श्रीगंगानगर तक ले जाया जाएगा, तथा उसे वर्तमान में सतलज और ब्यास से जल ले जाने वाली इंदिरा गांधी नहर से जोड़ा जाएगा।’’

मुख्यमंत्री आज सांचौर में

जालोर, 17 जून (कासं)।राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 18 जून को जालोर जिले के दौरे पर रहेंगे।

प्राप्त कार्यक्रमानुसार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 18 जून को दोपहर 12.25 बजे पुलिस लाइन हैलीपेड राजसमन्द से हेलीकॉप्टर के माध्यम से रवाना होकर दोपहर 1.25 बजे हैलीपेड सीलू, सांचौर पहुँचेंगे। इसके बाद दोपहर 1.30

■ वे सीलू घाट (नर्मदेश्वर) का पूजन व दर्शन करेंगे, फिर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत सभा में शामिल होंगे।

बजे हैलीपेड से कार द्वारा रवाना होकर दोपहर 1.35 बजे सीलू घाट, सीलू पहुँचेंगे, जहां वे सीलू घाट (नर्मदेश्वर) पर पूजन एवं दर्शन करेंगे। इसके उपरांत वे दोपहर 1.50 बजे वन्दे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कार्यक्रम व सभा में सम्मिलित होंगे। दोपहर 2.30 बजे सीलू घाट से हैलीपेड के लिए रवाना होंगे। दोपहर 2.35 बजे हैलीपेड से हेलीकॉप्टर द्वारा उत्तरलाई एयरपोर्ट बाड़मेर के लिए प्रस्थान करेंगे।

‘कुछ देर में परीक्षा शुरू हो रही है, मामले की सुनवाई नहीं हो सकती’

जयपुर, 17 जून। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 में दखल देने से इनकार कर दिया है। अवकाशकालीन न्यायाधीश मनीष शर्मा की एकलपीठ ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि कुछ देर में परीक्षा शुरू होने वाली है। ऐसे में अब मामले की सुनवाई नहीं की जा सकती है।

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि आरपीएससी की ओर से 17 और 18 जुलाई को आरएएस भर्ती-2024 की मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है,

■ हाई कोर्ट ने आरएएस 2024 की परीक्षा में दखल देने से इंकार किया।

जबकि फिलहाल आरएएस भर्ती-2023 की भर्ती प्रक्रिया ही पूरी नहीं हुई है। इस समय, उस परीक्षा के वर्तमान में साक्षात्कार कर चले हैं। ऐसे में बीते साल की इस परीक्षा की प्रक्रिया पूरी होने तक आरएएस-2024 की मुख्य परीक्षा को स्थगित किया जाए। याचिका में यह भी कहा गया कि प्रदेश के दोनों उपमुख्यमंत्री, एमएलए और एमपी मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की सिफारिश कर चुके हैं। उनकी सिफारिशों को देखते हुए परीक्षा स्थगित होने के निर्णय का इंजाज करने के बाद अंतिम समय पर याचिका दायर की गई है। याचिका में यह भी कहा गया कि भारत– (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप जी 7 शिखर वार्ता को बीच में छोड़कर अचानक अमेरिका रवाना हुए

वे ईरान-इज़रायल युद्ध में अमेरिका की भूमिका के बारे में अहम् निर्णय लेने की बात कहकर कैनडा से रवाना हुए

–अंजन रॉय–
–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–
ऑटवा,(कैनडा),17 जून। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कैनडा की रॉकी पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित बैनफ में हो रहे 7 शिखर सम्मेलन को अचानक छोड़ कर स्वदेश लौट गए, ताकि वे मध्य पूर्व में ईरान से जुड़े गंभीर और तात्कालिक हालात से निपट सकें। इससे पहले, इज़राइल ने ईरान के भीतर हमले कर उसके परमाणु हथियारों की क्षमताओं को नष्ट करने की कोशिश की थी।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए तेहरान के नागरिकों से सुरक्षा की खातिर तुरंत शहर छोड़ने की अपील की है। रिपोर्टों के अनुसार, ईरान के नागरिक भयभीत हैं और राजधानी एवं आसपास के इलाकों से कैसियन सागर की ओर पलायन कर रहे हैं। वहीं, पेट्रोल पंपों और जरूरी सामान की दुकानों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप इस समय ईरान संकट से जुड़े कुछ बेहद अहम फैसलों के बीच

■ इज़रायल ने पिछली रात ईरान पर पुनः भारी अटैक किया तथा ईरान की न्यूक्लियर सुविधाओं को एकदम नेस्तानाबूद करने के कगार पर है।

■ पर, धार्मिक शहर कोम के पर्वतों में जमीन के 250 से 300 फीट नीचे बनी सुरंगों में अभी भी ईरान के कुछ न्यूक्लियर प्रतिष्ठान सुरक्षित हैं।

■ इन सुरंगों को नष्ट करने के लिए इज़रायल को अमेरिका द्वारा प्रदत्त ‘‘बंकर बस्टिंग बम’’ के इस्तेमाल की अनुमति की आवश्यकता है और ‘‘बंकर बस्टिंग बम’’ केवल अमेरिका के बी-52 विमान ही युद्ध स्थल तक ले जा सकते हैं, दागने के लिए।

■ अभी तक अमेरिका ने इन बमों और बी-52 विमानों को ईरान के खिलाफ उपयोग में लाने के लिए अपनी इजाज़त नहीं दी थी।

में हैं। इज़राइल, ईरान के पवित्र शहर कोम के पास स्थित पहाड़ियों के अंदर बने सबसे महत्वपूर्ण परमाणु ठिकाने को तबाह करने की योजना पर विचार कर रहा है। सैटेलाइट चित्रों से पता चलता है कि ये ठिकाने लगभग 250 से 300

फीट गहराई में स्थित हैं।

इस संबंध में बंकर–बस्टिंग बमों (भूमिगत ठिकानों को नष्ट करने वाले विशेष बम) के इस्तेमाल पर विचार किया जा रहा है। केवल अमेरिका के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कच्चे तेल के परिवहन के लिए 1 0 0 टैंकर बनाएगा भारत

दस अरब डॉलर की लागत की इस परियोजना से भारत कच्चे तेल परिवहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा

■ टैंकरों के निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र की शिपयार्ड कम्पनियों कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और मद्रासगंव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ-साथ निजी क्षेत्र की कम्पनी स्क्वां डिफेंस एण्ड हैवी इंडस्ट्रीज की भागीदारी होगी।

■ कुछ आलोचकों का कहना है कि यह टैंकर भले ही सरकारी नियंत्रण में बनेंगे, इसका वास्तविक नियंत्रण धीरे-धीरे निजी हाथों में जा सकता है, खासकर रिलायंस और अडानी समूह के।

का, जटिल नौसेना व वाणिज्यिक जहाज परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने का रिकॉर्ड है, वहीं, स्क्वां डिफेंस (पूर्व में रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग) की भागीदारी निजी क्षेत्र की वापसी का संकेत देती है, जिसकी ऐतिहासिक संबद्धता अनिल अंबानी से रही है।

सार्वजनिक और निजी शिपयार्ड की इस रणनीतिक भागीदारी का उद्देश्य औद्योगिक क्षमता का संतुलित वितरण करना है, जो समुद्री आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के सरकार के व्यापक

प्रयासों को दर्शाता है।

इन टैंकरों का स्वामित्व सीधे शिपयार्ड या तेल कंपनियों के पास नहीं होगा, बल्कि स्पेशल पर्पज व्हील्स (एस.पी.वी.) के माध्यम से होगा। इन एस.पी.वी. में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एस.सी.आई.), सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों और वित्तीय संस्थानों की हिस्सेदारी होगी। हालांकि, परियोजना की कुल पूंजी का लगभग 70 प्रतिशत ऋण के माध्यम से जुटाया जाएगा, जिससे निजी वित्त पोषकों को अवसर मिलेगा और

संभावित रूप से इन महत्वपूर्ण मैरिटाइम एसेट्स (समुद्री परिसंपत्तियों) पर अप्रत्यक्ष निजी नियंत्रण भी बन सकता है।

हालांकि यह योजना सरकारी नेतृत्व में है, लेकिन इसका वास्तविक लाभ देश के दो सबसे बड़े व्यापारिक समूहों–रिलायंस इंडस्ट्रीज और अडानी ग्रुप–को मिल सकता है।

मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस को अनेक माध्यमों से लाभ होने की संभावना है। स्क्वां डिफेंस की भागीदारी, इसके पूर्व के संबंधों के माध्यम से 2 जहाज निर्माण अनुबंध मिलने की संभावना को दर्शाती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि, जामनगर स्थित रिलायंस की विशाल रिफाइनिंग गतिविधियाँ, इन नए टैंकरों में से कई को चार्टर करेगी, जिससे कच्चे तेल के परिवहन पर कंपनी का संचालन नियंत्रण हो सकता है।

दूसरी ओर, गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह को, विशेष रूप से अडानी पोर्ट्स (जैसे मुंद्रा पोर्ट) (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नाबालिग का अपहरण, दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा

जयपुर, 17 जून। जिले की पाँक्सो मामलों की विशेष अदालत ने करीब 14 साल की नाबालिग विवाहिता का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त नितिन कुमार को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने 24 वर्षीय इस अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया

■ पाँक्सो मामलों की विशेष अदालत ने सजा के साथ एक लाख रुपये जुर्माना लगाया।

है। पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान में नाबालिगों के साथ लैंगिक अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अदालत का कर्तव्य है कि अभियुक्त को उसके किए गए अपराध के लिए दंडित करें। अभियोक्त पक्ष की ओर से विशेष (शेष अंतिम पृष्ठ पर)